Delhi Police have reported that all the Assistant Commissioners of Police/ S.H.Os. have been directed to keep their staff alert and take stern action against the encroachers and also inform the concerned land owning agency about any encroachments for their removal.

Printing of Money Order Forms

2879. DR. MOHAN BABU: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the pending orders of the Directorate of Printing for Money Order forms and A.D. cards etc. pertaining to the Department of Posts as on 31st March, 1998 lying with various Government Presses; and

(b) the reasons for delay in printing?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): (a) The orders for Money Order Forms (M O - 8) and A.D. Cards (R P - 54) pertaining to the Department of Posts as on 31.3.98 pending in the Government of India Presses are 26,14,720 pads and 3,64,96,000 respectively.

(b) The reasons for delay in printing of Money Order Forms and A.D. Cards are as follows:—

(i) Annual production capacity of the Presses is getting reduced every year due to natural wear and tear.

(ii) Short & erratic supply of electricity by the State Electricity Boards results in idling of machines.

(iii) The Presses also undertake printing jobs of other Ministries/Departments on priority basis. Due to change in priority of the printing jobs, all works cannot be completed strictly on first come first serve basis.

दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ियों में जनसंख्या

2880. **श्री जनेश्वर मिश्र: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ियों में कुल जनसंख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए आये दिन कहीं न कहीं किसी न किसी जगह झुग्गी-झोपड़ियों को उजाड़ दिया जाता है;

(ग) इन झुग्गी-झोपड़ियों में कौन-कौन सी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा कौन सी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं; और

(घ) इन झुग्गी-झोपड़ियों में इलाज तथा शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) दिल्ली नगर निगम के स्लम विभाग ने बताया है कि 1994 में किए गए मूल्यांकन के अनुसार 20 लाख से अधिक लोग 1080 झुग्गी-झोपड़ी समूहों में रह रहे थे।

(ख) और (ग) फिलहाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा झुग्गी-झोपड़ी निवासियों की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली नगर निगम के स्लम विभाग के माध्यम से निम्नलिखित त्रिआयामी योजना चलाई जा रही है:—

(i) सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए तत्काल अपेक्षित भूमि से पात्र झुग्गी-झोपड़ी निवासियों (जो जनवरी, 1990 को विद्यमान थे) का पुनः स्थान निर्धारण/पुनर्वास;

(ii) ऐसी सार्वजनिक भूमि, जो सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए रखी गई है किन्तु कार्यान्वयन के लिए उसकी तत्काल आवश्यकता नहीं है, पर स्थित झुग्गी-झोपड़ी समूहों में न्यूनतम बुनियानी सुविधाएं मुहैया कराना;

(iii) सार्वजनिक भूमि जो किसी परियोजना के लिए नहीं रखी गई है तथा जिसकी निकट भविष्य में आवयश्यकता नहीं है, उस भूमि पर स्थित झुग्गी-झोपड़ी समूहों का भूस्वामी एजेंसियों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने के बाद उसी स्थान पर उन्नयन।